सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक: 23 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, मंगलवार 24 फरवरी, 2026
मूल्य ₹ 3/-

यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है।
-प्लेटो

अब फुटबाल के नये नियमों से नाराज हुए... 7 | आरटीआई की धार से सत्ता पर... 3 | भाजपा राज में विकास नहीं सिर्फ... 2

जंग के साये में इजरायल की ओर पीएम मोदी का कदम

मोदी के संबोधन से पहले इजरायल में सियासी संग्राम

» कूटनीति विफलता!, भारत की तटस्थता दांव पर?
» यात्रा की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल क्या यह सही समय है?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जब दुनिया का हर जिम्मेदार राष्ट्र जंग के मुहाने पर खड़े ईरान-अमेरिका-इजरायल की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो तब अगर कोई देश उसी आग की तरफ बढ़ता दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इजरायल यात्रा ऐसे ही सवालों के केंद्र में है। पीएम मोदी का इजरायल का राजनयिक दौरा नहीं है यह एक ऐसा संकेत है जो भारत की दशकों पुरानी तटस्थ विदेश नीति, उसकी नैतिक स्थिति और उसकी रणनीतिक संतुलन क्षमता तीनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

पश्चिम एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजरायल के बीच खुले टकराव की स्थिति है। मिसाइलें गिर रही हैं चेतावनियां जारी हो रही हैं और दुनिया के बड़े राष्ट्र युद्ध को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का इजरायल जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है। और यह संदेश क्या है? क्या यह भारत की तटस्थता का अंत है? या फिर यह भारत की विदेश नीति का नया चेहरा है जहां रणनीतिक लाभ के लिए नैतिक संतुलन को पीछे छोड़ दिया गया है?

अरब देशों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है असर

भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। लेकिन इस यात्रा से यह संदेश जा सकता है कि भारत इस संघर्ष में एक पक्ष के अधिक करीब खड़ा है। इससे भारत की उस छवि को नुकसान पहुंच सकता है जो उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ और शांति समर्थक राष्ट्र के रूप में स्थापित करती रही है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा अरब देशों से पूरा होता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देश भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार हैं। इसके अलावा, इन देशों में 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं।

इजरायल भारत द्विपक्षीय रक्षा समझौते को बढ़ाने की योजना

भारत में इजरायल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजरायल भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके और भारत में मिलिट्री हार्डवेयर बनाया जा सके। साथ ही लेटेस्ट आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग बढ़ाया जा सके। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर रेवाच ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते इजरायल जा रहे हैं। इजरायल और भारत के बीच खास संबंधों को समझना जरूरी है और हम आज भारत को एक ग्लोबल सुपरपावर के तौर पर देखते हैं। इजरायल के इस दौरे के बारे में एक कैबिनेट प्रस्ताव भी है और यह कुछ पहलुओं, राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा प्रस्तावों पर ध्यान देगा।

कूटनीति में विश्वास सबसे जरूरी

यदि भारत की विदेश नीति एकतरफा दिखाई देती है तो इसका असर इन संबंधों पर पड़ सकता है। कूटनीति में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है, और किसी भी संकेत से यह विश्वास कमजोर हो सकता है। इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना भी माना जा रहा है। भारत और इजरायल के बीच पहले से ही ड्रोन, मिसाइल और निगरानी तकनीक के क्षेत्र में सहयोग है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही समय है जब भारत अरबों रुपये के नए रक्षा समझौते करे?

विदेश नीति की आत्मा की परीक्षा

यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है। यह भारत की विदेश नीति की आत्मा की परीक्षा है। और यह परीक्षा तय करेगी कि भारत एक संतुलित वैश्विक शक्ति बना रहेगा या फिर किसी एक ध्रुव की ओर झुकता हुआ दिखाई देगा। कूटनीति में सिर्फ निर्णय ही नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर हो जब मिसाइल हमले और सैन्य जवाबी कार्रवाई जारी हो तब किसी एक पक्ष की यात्रा करना स्वाभाविक रूप से तटस्थता पर सवाल खड़े करता है।

भारत हमेशा शांति समर्थक रहा है

भारत हमेशा से खुद को शांति का समर्थक और संवाद का पक्षधर बताता रहा है। अमेरिका और रूस जैसे परस्पर विरोधी गुटों के साथ संतुलन बनाना भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है। यही संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और स्वतंत्र शक्ति बनाता रहा है। लेकिन इजरायल की इस यात्रा की टाइमिंग उस संतुलन को कमजोर करती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अरब देशों खासतौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के ऐतिहासिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं, तब क्या यह यात्रा उन रिश्तों को जोखिम में डाल सकती है? क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और करोड़ों प्रवासी भारतीयों के भविष्य को एक रणनीतिक सौदे के लिए दांव पर लगा रहा है? यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था और उसके रक्षा माडल पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस सुरक्षा तकनीक को अभेद्य बताया जाता था वह हालिया संघर्षों में आलोचना के घेरे में है। ऐसे में भारत द्वारा अरबों रुपये के रक्षा समझौतों की संभावनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या भारत सही समय पर सही निर्णय ले रहा है या फिर जल्दबाजी में एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका असर आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा?

भारत की तटस्थ छवि पर खतरा

भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान संतुलित रुख अपनाकर वैश्विक स्तर पर सम्मान हासिल किया था। भारत ने न तो खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही पश्चिमी दबाव में आया। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन इजरायल यात्रा की टाइमिंग इस संतुलन को कमजोर कर सकती है। इससे भारत की नॉन अलाइनमेंट 2.0 नीति पर सवाल उठ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है बल्कि इसका घरेलू राजनीतिक संदेश भी है। सरकार इसे भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन विपक्ष और आलोचक इसे एक जोखिम भरा कदम बता रहे हैं। कूटनीति में हर कदम का संदेश होता है दोस्तों के लिए भी और विरोधियों के लिए भी।

क्या भारत अपनी पारंपरिक नीति से भटक रहा है?

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान उसका संतुलन रही है। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, लेकिन साथ ही वैश्विक शांति और संतुलन का भी समर्थन किया है। पीएम का इजरायल दौरा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं है। यह भारत की विदेश नीति की दिशा और उसकी प्राथमिकताओं का संकेत है। यह दौरा नई तकनीक, रक्षा सहयोग और वैश्विक साझेदारी के रूप में भारत को रणनीतिक लाभ दे सकता है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी हैं तटस्थता की छवि, अरब देशों के साथ संतुलन, और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका। इतिहास ऐसे फैसलों को सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि उनके परिणामों से आंकता है।

इजरायल में विवाद

नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित इजरायली संसद संबोधन से पहले ही इजरायल की राजनीति में विवाद गहरा गया है। इजरायल के विपक्ष ने साफ संकेत दिया है कि यदि देश के मुख्य न्यायाधीश को संसदीय सत्र में आमंत्रित नहीं किया गया, तो वे इस संबोधन का विरोध करेंगे। इजरायल के मुख्य विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस मुद्दे को संवैधानिक परंपराओं और संस्थागत सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के संसद संबोधन के दौरान न्यायपालिका प्रमुख की मौजूदगी एक स्थापित परंपरा रही है। उनका आरोप है कि इस परंपरा का पालन न करना सरकार द्वारा संस्थाओं को कमजोर करने का संकेत है। इस विवाद ने इजरायल के भीतर पहले से चल रहे न्यायपालिका बनाम सरकार के टकराव को और उजागर कर दिया है। विपक्ष का मानना है कि यह केवल प्रोटोकॉल का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का प्रश्न है। इस बीच, पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में रक्षा, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। हालांकि, संसद संबोधन से पहले पैदा हुआ यह विवाद इस दौरे को राजनीतिक रूप से अधिक संवेदनशील बना रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इजरायल सरकार प्रोटोकॉल परंपरा का पालन करती है या विपक्ष इस मुद्दे को और बड़ा राजनीतिक संकट बना देता है।

भाजपा राज में विकास नहीं सिर्फ घोटालों की इमारत : अखिलेश यादव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नाम पर विकास का एक भी ठोस काम दर्ज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का असली चेहरा घोटालों, भ्रष्टाचार और झूठे दावों के सहारे सत्ता में बने रहने का है, जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच चुका है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद सड़कों और सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कुछ ही महीनों में जवाब दे रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोंच में 23 लाख रुपये की लागत से बनी सीसी रोड दो महीने के भीतर ही उखड़ने लगी, जबकि महोबा के उखरा गांव में 35 लाख रुपये की लागत से बन रही सड़क की परतें शुरू में ही टूटने लगीं। इसी तरह पानी की टंकियां बनते ही गिर जा रही हैं, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रमाण है।

हिरासत में हो रही मौतों पर उठाये सवाल

कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हिरासत में मौतों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी, शिक्षक और आम नागरिक सभी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर संविधान और लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गड्ढामुक्त सड़क का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि आज सड़कें गड्ढों में बदल चुकी हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गड्ढे भरने के नाम पर बजट तो खर्च कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बदतर होते चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और नौजवान नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। भर्ती परीक्षाएं या तो रद्द हो जाती हैं या उनके परिणाम रोक दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी मांगने वाले युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाठियों से जवाब दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उन्होंने पूरी तरह विफल बताया और कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है, जबकि अस्पतालों में दवा और इलाज दोनों का अभाव है।

मतदाता सूची पर सियासत गरम

सपा ने लगाया नाम काटने की साजिश का आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने राज्य के कई जिलों में अपने समर्थक मतदाताओं के नाम कथित रूप से साजिश के तहत एसरकार द्वारा काटे जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत भेजकर पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

चुनाव आयोग से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

सपा के अनुसार, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, बहराइच, देवरिया, आजमगढ़, कन्नौज और भदोही समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए हैं। इन फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पार्टी का आरोप है कि इन फॉर्म-7 में कई मामलों में आवेदकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं और यह प्रक्रिया एक सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है, जिससे विशेष समुदाय और सपा समर्थक मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सके।

सपा की शिकायत में फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग बूथों पर क्रमशः 80, 87, 46 और 63 फॉर्म-7 जमा किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी तरह आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ संख्या-208 पर भी बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए, जिनमें

कई जिलों में फर्जी फॉर्म-7 का आरोप, हस्ताक्षर तक संदिग्ध

आवेदकों के हस्ताक्षर तक नहीं थे। कन्नौज के तिर्वा विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट मतदाता सूची से काटे गए नामों को जोड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म-6 जमा करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या-339 के 498 मतदाताओं को उनके मूल बूथ से हटाकर 10 किलोमीटर दूर दूसरे बूथ से जोड़ दिया गया है, जिससे मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार बहराइच और देवरिया में भी बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा कर मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि भाजपा के पदाधिकारी बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में मतदाता सूची तैयार कराने की

मुस्लिम और पीडीए मतदाताओं को निशाना बनाने का आरोप

कोशिश कर रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में जिन लोगों के नाम हटाने के लिए आवेदन किया गया है, वे अभी भी अपने दर्ज पते पर रह रहे हैं और जीवित हैं। यहां तक कि कुछ आवेदकों ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग

सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पार्टी ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची को ब्लॉक, तहसील और पंचायत भवनों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाए, ताकि मतदाता अपने नाम की पुष्टि कर सकें और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत कर सकें। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग इस मामले में मूकदर्शक बना हुआ है, जबकि लाखों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

ईरान में फंसे भारतीय छात्रों पर संकट परीक्षाएं और सुरक्षा के बीच कठिन विकल्प

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ईरान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के सामने सुरक्षा और भविष्य दोनों को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने छात्रों की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कराने और उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।

एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा हालात में छात्र असमंजस और भय के माहौल में जी रहे हैं। एक तरफ उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में छात्रों के सामने पढ़ाई जारी रखने या अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश लौटने का कठिन विकल्प खड़ा हो गया है। इस बीच भारतीय दूतावास, तेहरान ने भी एडवाइजरी जारी कर ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जारी की गई है जिससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएं और गहरा गई हैं। समस्या यह है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान के मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल संस्थानों में अध्ययनरत हैं। उनकी विश्वविद्यालय परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा नजदीक होने के कारण कई छात्र तत्काल वापसी का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं, रुकने का मतलब संभावित सुरक्षा जोखिम उठाना है।

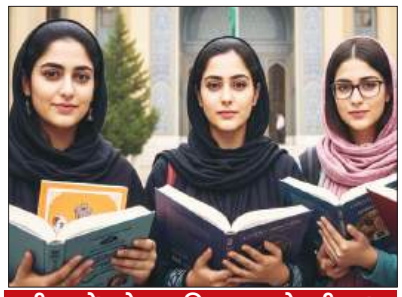

परीक्षाओं को स्थागित कराने की मांग

छात्रों और उनके परिजनों ने सरकार से मांग की है कि वह ईरानी विश्वविद्यालयों से समन्वय कर परीक्षाएं स्थगित कराने या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही, जरूरत पड़ने पर विशेष उड़ानों के माध्यम से छात्रों की सुरक्षित वापसी कराई जाए। यह स्थिति एक बार फिर विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा को लेकर भारत की कूटनीतिक जिम्मेदारी और तत्परता की परीक्षा बन गई है।

छत्तीसगढ़ की सरकार आज पेश करेगी बजट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार आज बजट 2025-26 को पेश करेगी। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पांच साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करना है।

विकास, सुरक्षा और बस्तर पर विशेष नजर

जीडीपी को इन पांच वर्षों में दोगुना करके 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए हम राज्य के समृद्ध संसाधनों को आर्थिक वृद्धि और विकासशील बनाने के लिए प्रगतिशील नीतियों के साथ जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं। रोजगार को सीएम साय ने के मुताबिक बजट में ऐस प्रावाधान किये गये है जिससे रोजगार के मौके बनें इसके लिए हमने नई औद्योगिक नीति बनाई। इसके तहत बीते 15 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के समझौते प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा सेंटर, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और साथ ही मेडिकल टूरिज्म फोकस हमारे लिए फोकस के क्षेत्र हैं। साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ, किसी भी राज्य को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए।

फिर सामने आया नीले ड्रम का खौफ

लखनऊ में मर्डर से सनसनी, बेटे ने बाप को मार कर ड्रम में छिपाया शव, शव के टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। जिस घर में कभी परिवार, कारोबार और सपनों की आवाजें गूंजती थीं, वहीं अब सन्नाटा, सनसनी और सवालों का बोझ पसरा है।

एक 20 वर्षीय बेटे द्वारा अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर देना और फिर शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में छिपा देना यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि टूटते पारिवारिक संवाद मानसिक दबाव और रिश्तों में पनपती खामोश दरारों की भयावह तस्वीर भी है।

45 वर्षीय शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या उनके बेटे अक्षय प्रताप सिंह ने लाइसेंसी रायफल से की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के हाथ पैर अलग कर दिए और शरीर के ऊपरी हिस्से को घर की तीसरी मंजिल पर रखे एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया। घर से 20 लीटर एसिड का गैलन भी बरामद हुआ है जिससे आशंका है कि वह सबूत मिटाने की तैयारी में था।

गुमशुदगी की आड़ में रची गई कहानी

सोमवार सुबह अक्षय खुद आशियाना कोतवाली पहुंचा और पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने बताया कि 20 फरवरी की सुबह उसके पिता दिल्ली जाने के लिए निकले थे और लौटे नहीं। मोबाइल फोन बंद होने की बात कहकर उसने अनहोनी की आशंका जताई। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी का लगा लेकिन जब उसने घर लौटकर पिता के मित्र सोनू गुप्ता को आत्महत्या की बात बताई तो उसके विरोधाभासी बयान ने पुलिस को सतर्क कर दिया। कड़ाई से पूछताछ में अक्षय टूट गया। उसने स्वीकार किया कि 20 फरवरी की शाम करीब 4:30 बजे करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पिता से विवाद हुआ। कहासुनी बढ़ी और गुस्से में उसने घर में रखी लाइसेंसी रायफल से गोली चला दी। गोली लगते ही मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या के बाद जो कुछ हुआ वह और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। आरोपी ने शव के टुकड़े किए हाथ पैर अलग कर दिए और ऊपरी हिस्सा ड्रम में छिपा दिया। तीसरी मंजिल से बरामद ड्रम से शव का हिस्सा मिला है जबकि अन्य अंगों की तलाश जारी है। फोरेंसिक टीम ने घर को सील कर साक्ष्य जुटाए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि अक्षय ने अपनी 17 वर्षीय बहन कृति को धमकी दी थी कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए। डर के साए में वह कई दिनों तक चुप रही। पुलिस अब उसका बयान दर्ज कर रही है।

आरटीआई की धार से सत्ता पर वार करेगी कांग्रेस

डाटा संरक्षण जैसे प्रावधानों के नाम पर सूचनाओं को दबाया जा रहा है

आरटीआई की ताकत वापस लाएगी कांग्रेस

- कांग्रेस का बड़ा दांव आरटीआई तंत्र को पुनर्जीवित करने की तैयारी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का प्रस्ताव
- मनरेगा के बाद आरटीआई को टुकड़ों टुकड़ों में कमजोर कर रही है केन्द्र सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश की राजनीति में सूचना का अधिकार एक बार फिर केंद्र में आ गया है। जिस कानून को कभी पारदर्शिता का सबसे ताकतवर औजार कहा गया था, वही अब सियासी संग्राम का नया मोर्चा बनने जा रहा है। कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह आरटीआई तंत्र को महज एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध के सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून को टुकड़ों टुकड़ों में कमजोर कर रही है और इसे मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली गई है।

वहीं एआईसीसी विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरटीआई अधिनियम ने देश में पारदर्शिता की नई दिशा दी थी लेकिन अब डेटा संरक्षण जैसे प्रावधानों के नाम पर सूचनाओं को दबाया जा रहा है। उनके मुताबिक यह केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि जवाबदेही की भावना को कमजोर करने की सुनियोजित प्रक्रिया है। सिंहवी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य आरटीआई कानून को उसकी मूल ताकत और स्वरूप में बहाल करना है और इसके लिए पार्टी सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।

आक्रामक रणनीति की रूपरेखा

कुल मिलाकर, आरटीआई को लेकर कांग्रेस ने एक व्यापक और आक्रामक रणनीति की रूपरेखा पेश कर दी है। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव से लेकर अदालत तक डिजिटल डायरेक्टरी से लेकर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तक—यह पहल केवल कानून की बहाली की मांग नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान किस हद तक जनसमर्थन जुटा पाता है और क्या आरटीआई वास्तव में फिर से देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन पाता है।

राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का प्रस्ताव

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर एक भव्य कॉन्क्लेव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कॉन्क्लेव में पूर्व नौकरशाहों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और नीति विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि यह आयोजन केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि एक वैचारिक विमर्श का मंच बनेगा, जहां आरटीआई कानून के वर्तमान स्वरूप, उसके कमजोर किए जाने और उसे मजबूत करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के बाद एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा और देशभर के विधायकों, नीति-निर्माताओं तथा नागरिक समूहों के साथ साझा किया जाएगा।

बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है। एक ओर पार्टी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर वह कानूनी मोर्चे पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आरटीआई को राजनीतिक तीर के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में सूचना से जुड़े मुद्दे चुनावी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस इस अभियान के जरिए युवाओं और सिविल सोसाइटी को जोड़ना चाहती है। लीगल फेलोज़ प्रोग्राम और पॉडकास्ट श्रृंखला के माध्यम से पार्टी कानून के छात्रों, युवा अधिवक्ताओं और जागरूक नागरिकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पार्टी का कानूनी ढांचा मजबूत होगा और आरटीआई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वैचारिक समर्थन भी मिलेगा।

रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की अवधारणा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इन पहलों को पार्टी और उसकी विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए पूर्ण वित्तीय समर्थन का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि पारदर्शिता और जवाबदेही की लड़ाई कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता का हिस्सा रही है और इसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की अवधारणा भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम पांच वकीलों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि जमीनी स्तर पर कई नेता और कार्यकर्ता दबाव और धमकियों का सामना करते हैं, ऐसे में उन्हें त्वरित कानूनी सहयोग उपलब्ध कराना जरूरी है। विभिन्न राज्यों से नाम जुटाकर एक डिजिटल डायरेक्टरी तैयार की जा रही है और चयनित वकीलों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

अदालत का सहारा लेगी कांग्रेस

सिंहवी ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में याचिका दायर करेगी और स्वयं अदालत में पेश होकर पैरवी करेंगे। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे कानूनी और संवैधानिक विमर्श का हिस्सा बनाना चाहती है।

सूचना के अधिकार को लेकर बहस तेज

यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब सूचना के अधिकार को लेकर बहस तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि संशोधनों और प्रशासनिक प्रावधानों के जरिए आरटीआई की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता कम की गई है। पार्टी का मानना है कि यदि सूचना का अधिकार कमजोर होता है तो लोकतंत्र की बुनियाद भी हिलती है, क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही ही लोकतांत्रिक शासन की आत्मा हैं।

सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे

सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहते हुए एआईसीसी विधि विभाग ने चार नए कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। इनमें लीगल फेलोज प्रोग्राम, विधि-मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग की पॉडकास्ट श्रृंखला, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और 'आरटीआई अधिनियम को पुनः प्राप्त करने' के लिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य युवा वकीलों के साथ जुड़ाव बढ़ाना, कानूनी नेटवर्क को पुनर्जीवित करना और उन आवाजों को मंच देना है जो आरटीआई के कथित कमजोर किए जाने के खिलाफ खड़ी हैं।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा क्या सिर्फ सलाह जारी करने तक सीमित?

क्या भारत की कूटनीति अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सच में तैयार है या सिर्फ संकट के बाद सलाह जारी करना ही उसकी मजबूरी बन गई है? भारत आज सिर्फ एक भौगोलिक सीमा तक सीमित देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक मानव शक्ति का केंद्र बन चुका है। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक। भारतीय हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में हर संकट भारत की परीक्षा बन जाता है।

दुनिया के किसी भी कोने में जब गोली चलती है जब दंगे भड़कते हैं जब युद्ध की आग सुलगती है तो उसकी तपिश भारत तक महसूस होती है। वजह साफ है। आज करोड़ों भारतीय अपने सपनों रोजगार और भविष्य की तलाश में विदेशों में बसे हैं। मेक्सिको में कार्टेल सरगना की मौत के बाद भड़की हिंसा और वहां रह रहे भारतीयों को जारी एडवाइजरी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की कूटनीति अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सच में तैयार है या सिर्फ संकट के बाद सलाह जारी करना ही उसकी मजबूरी बन गई है? भारत आज सिर्फ एक भौगोलिक सीमा तक सीमित देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक मानव शक्ति का केंद्र बन चुका है। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक। भारतीय हर जगह मौजूद हैं। ऐसे में हर संकट भारत की परीक्षा बन जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों भारतीय छात्रों को निकालने की चुनौती हो या कुवैत और यमन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों की सुरक्षित वापसी। हर बार भारत की कूटनीति पर दुनिया की नजर रही है।

समस्या की जड़ यह है कि भारतीय नागरिक अक्सर बिना पर्याप्त सुरक्षा जानकारी बिना स्थानीय जोखिम समझे विदेशों में चले जाते हैं। लाखों छात्र और मजदूर ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता, संगठित अपराध या युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में केवल एडवाइजरी जारी करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है एक मजबूत, पूर्व-नियोजित और तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र की है। भारत को अब अपनी कूटनीति को तीन स्तरों पर मजबूत करना होगा। पहला- रोकथाम इसका मतलब है कि विदेश जाने वाले हर भारतीय को जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा प्रशिक्षण और रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ा जाए। दूसरा-तत्काल प्रतिक्रिया हर देश में भारतीय दूतावासों को सिर्फ कागजी कार्यालय नहीं बल्कि संकट प्रबंधन केंद्र बनाया जाए। तीसरा-रणनीतिक दबाव भारत को उन देशों के साथ ऐसे समझौते करने होंगे जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को कानूनी और प्रशासनिक रूप से सुनिश्चित करें। आज भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जनसंख्या और उसकी वैश्विक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। लेकिन वैश्विक शक्ति बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी है। चाहे वह दिल्ली में हों या दुबई में लखनऊ में हों या लंदन में। आने वाले समय में यह सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि जब कोई भारतीय विदेश में संकट में फंसता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दांव पर होती है। अब समय आ गया है कि भारत सिर्फ संकट का जवाब देने वाला देश नहीं, बल्कि संकट को पहले से रोकने वाला वैश्विक संरक्षक बने। यही एक सच्चे वैश्विक भारत की पहचान होगी।

संजय

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

वॉशिंगटन में भारतीय हितों की रक्षा के निहितार्थ

ज्योति मल्होत्रा

अमेरिका में हमारा आदमी वह नहीं है जिसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, दरअसल, वह उनका सहयोगी है यानि भारत में अमेरिका के राजदूत, सर्जियो गोर। यह शख्स बहुत ज्यादा रोचक है। वे 1986 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, बतौर पूर्व सोवियत यूनियन नागरिक पैदा हुए थे (नाम सर्जियो गोरोखोव्स्की रखा गया); एक दशक के अंदर उनका परिवार अमेरिका चला गया, जहां उन्होंने अपना सरनेम छोटा कर लिया। उम्र के चालीस साल पूरे करने से पहले ही श्रीमान गोर न केवल दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी बने हुए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस तक पहुंचने वाले रास्ते की मुश्किलें आसान बनाने में वे भारत की हर संभव मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मेरी बात याद रखिए, अगले गणतंत्र दिवस पर वे एक उच्च पद्म सम्मान के पक्के दावेदार होंगे।

अब श्रीमान गोर की शोहरत का दावा सिर्फ उस धमाकेदार खबर पर नहीं टिका है, जो उन्होंने बीते शुक्रवार दिल्ली में ब्रेक की थी, अर्थात, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बहुत जल्द भेंट हो सकती है; यह देखते हुए कि ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान '11 बहुत महंगे' लड़ाकू जेट मार गिराए गए थे, भारत निश्चित रूप से इस पर नजर रखेगा। माना जाता है कि गोर ने भारत के विरुद्ध अड़ियल रवैया अपनाए बैठे अमेरिकी प्रशासन को अंततः व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया है - और भारत को 50 फीसदी टैरिफ की मुसीबत से राहत दिलवाई है, भले ही हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता के वारिस हैं। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि उन्होंने एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले पर भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक संगठन, 'पैक्स सिलिका' में प्रवेश पाने में भी मदद की है; मत भूलिए कि अमेरिकियों ने दो महीने पहले, दिसंबर में, इसी संगठन में भारत के लिए दरवाजे बंद करवा दिए थे। (तो हृदय परिवर्तन की वजह क्या है?)

अब आप दलील देंगे कि यह सब तो आमतौर पर होता रहता है, कि यह तो गोर का काम है कि वह स्थानीय लोगों, मतलब हम भारतीयों के साथ तालमेल बनाकर रखें - और यहां पर मैं यह शब्द सोच-समझकर सलाह के रूप में उपयोग कर रही हूं, क्योंकि आपने अब तक वह पढ़ लिया होगा जो गोर के काफी ताकतवर साथी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक हफ्ते

से भी कुछ पहले म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था। यह भाषण 'ईसाई आस्था' और 'पश्चिमी सभ्यता' जैसे विशेषणों से भरा हुआ था- और कक्ष में मौजूद सभी राजनेता, जिनमें से अधिकांश गोरे थे, उन्होंने जोश में तालियां बजाईं। यह और बात है कि इन्हीं में से कई लोग लगातार अलग-अलग रंगों की त्वचा वाले लोग- भूरे, काले, पीले- जोकि भारत और चीन जैसे तीसरी दुनिया के देशों में रहते हैं, उनके साथ व्यापार समझौते करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बाजार वहीं पर हैं। म्यूनिख में रुबियो के अनुसार, 'हमें अपनी राष्ट्रीय सीमाओं पर भी नियंत्रण करना होगा। यह नियंत्रण कि कौन और कितने लोग हमारे देशों में आते हैं, यह कोई जेनोफोबिया (परदेसियों का भय) दिखाना नहीं है। यह नफरत नहीं है। यह राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का एक बुनियादी काम है'। आपको क्यूबाई मूल के अमेरिकी की अमेरिका के झंडे 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' को लहराने की तीव्र या कुछ हद तक बेताब इच्छा की खातिर अवश्य ही तारीफ करनी होगी, किंतु विडंबना पर ध्यान दें। मार्को का क्यूबाई नागरिकता वाला परिवार उस वक्त तक अमेरिकी नागरिक नहीं बना था, जब 1971 में वे पैदा हुए थे। लेकिन, एक ताकतवर अमेरिकी विदेश मंत्री श्रीमान रुबियो ऐसा रुख अपना रहे हैं जो भविष्य के सुंदर पिचाई जैसों को अमेरिका में पैर जमाने की कोशिश करने में अड़चन बनेगा (भारत अपने 'सुंदर पिचाइयों' को घर पर ही क्यों नहीं रोककर रख सकता है, यह एक अच्छा और अलग सवाल है)। फिर मुक्त व्यापार की वह दलील जिसे पश्चिमी जगत सोवियत यूनियन के पतन और शीत युद्ध खत्म होने के बाद से आगे बढ़ा रहा है — यह मानना पड़ेगा कि इसी ने भारत को अपनी जटिल नीति में सुधार करने और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए मजबूर किया था और दक्षिणी गोलार्ध के मुल्कों ने अपने बाजार खोलने की एवज में, श्रमिकों के मुक्त आवागमन की मांग की थी।

अर्थात सबसे काबिल लोगों को उस जगह पर जाने की मुक्त आवाजाही की सहूलियत होनी चाहिए जहां जॉब्स हो ; महज पासपोर्ट के रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव न हो। क्योंकि पिछले साल ट्रंप ने मुक्त व्यापार की दलील को निरस्त कर दिया था, अब उनके विदेश मंत्री नए समझौते के प्रारूप को अंतिम रूप दे रहे हैं-हमारे सामान के लिए अपना बाजार खोलो, लेकिन हमसे यह उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे लोगों की नौकरियों के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था खोलेंगे।

मुआवजे के अलावा हादसे के दोषी भी दंडित हों

सवाल है कि क्या आर्थिक मुआवजा किसी जीवन की क्षति की पूर्ति कर सकता है? स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि कानून का भय और न्याय का विश्वास दोनों कायम रह सकें।

सुरेश सेठ

देश के सड़क ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है और राजमार्गों का जाल तेजी से फैला है। संकरी और जर्जर सड़कों की जगह अब आधुनिक एवं चौड़ी सड़कों ने ले ली है, जिससे सड़क परिवहन व्यवसायियों और आम नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बन गया है। किन्तु इस विकास के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। शहरों की भीड़भाड़ से दूर बाइपास और खुली सड़कों पर वाहन चालक प्रायः लापरवाही से तेज गति में वाहन चलाते हैं। पर्याप्त निगरानी और यातायात नियंत्रण के अभाव में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब चालक नशे की अवस्था में वाहन चलाते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन यात्रियों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं।

हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एशिया में सपाट और चौड़ी सड़कों पर दुर्घटनाओं की दर चिंताजनक रूप से बढ़ी है। भले ही सड़क सुरक्षा बल की तैनाती और दुर्घटना में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की हो, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है। यदि किसी एक चालक की लापरवाही से दूसरे चालक या राहगीर की मृत्यु हो जाती है, तो यह केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई मृत्यु का मामला है। ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोग कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में दखल या धनबल के सहारे राहत पा लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(एक्स) में 'पीड़ित' की परिभाषा में कानूनी वारिसों को भी शामिल किया गया है। पूर्व में प्रायः ऐसा होता था कि मृतक के वारिस समझौते के तहत मुआवजा स्वीकार कर लेते थे और मामला आगे नहीं बढ़ता था। फलस्वरूप, आर्थिक क्षतिपूर्ति को ही न्याय का विकल्प मान लिया जाता था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसे प्रत्यक्ष न्याय तो नहीं मिल सकता; अतः उसके परिजनों को धनराशि देकर मामले का पटाक्षेप कर दिया जाता था।

क्या केवल आर्थिक मुआवजा किसी जीवन की क्षति की पूर्ति कर सकता है? स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि कानून का भय और न्याय का विश्वास दोनों कायम रह सकें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला दिया है कि सड़कों पर लापरवाही से वाहन चला कर दुर्घटना करने वाले माफी के हकदार नहीं। निस्संदेह, मृतक के आश्रितों को कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए लेकिन यहां तो मौत के जिम्मेदार को ही माफ होने लगी। अदालत ने इस अधिकार रद्द कर दिया है।

कुछ अभियुक्तों ने तर्क दिया कि वे केवल अनुबंध पर वाहन चला रहे थे, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि वाहन स्वामी की है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोष तय करना अदालत का कार्य है; यह साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित होगा कि जिम्मेदार कौन है। यदि किसी वाहन स्वामी ने जर्जर वाहन सड़क पर उतारे हों और उनसे दुर्घटना हुई हो, तो जांच उसी अनुरूप की जाएगी। स्पष्ट है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही और तेज गति के कारण होती हैं। ऐसी मौतों की आपराधिक जवाबदेही केवल धन-लेनदेन के समझौते के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती। समझौते से एफआईआर रद्द करना तभी संभव है जब वास्तविक पीड़ित की शिकायत शेष न हो। पीड़ित के परिजनों के लिए न्याय सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। वर्तमान परिस्थितियों में कठोर दंड की संभावना प्रायः क्षीण प्रतीत होती है।

दंड विधान में भी कानूनी छिद्र खोज लेने वाले सामने आ जाते हैं। 'तारीख पर तारीख' की प्रक्रिया लंबी होती रहती है और अभियुक्त जमानत पर बाहर आकर स्वयं को अपराध मुक्त समझने लगते हैं। इसी व्यवस्था में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने दुर्घटनाओं में अपनी लापरवाही से हुई मौतों के मामलों का समाधान भी अपने तरीके से निकाल लिया-मुआवजे और समझौतों के माध्यम से। न्याय का सिद्धांत यह है कि अपराधी को दंड मिले और पीड़ित परिवार को न्याय। किसी की मृत्यु के बदले केवल धनबल के आधार पर, वारिसों के हस्ताक्षरों से 'माफी' स्वीकार करवा लेना न्याय की भावना के विपरीत है। यह निर्णय न केवल विधि के शासन को सुदृढ़ करता है, बल्कि लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ-न्यायपालिका-की गरिमा और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इसे स्वीकार और लागू करना ही न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम होगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि सड़कें वर्षों तक मरम्मत की प्रतीक्षा में जर्जर न पड़ी रहें। दुर्घटना-प्रवण ब्लैक स्पॉट्स को शीघ्र सुधारा जाए, चेतावनी संकेत स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लगाए जाएँ तथा रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो।

फैटी लीवर में ये चीजें भी हैं काफी नुकसानदायक

आमतौर पर जब हम फैटी लीवर की बात करते हैं, तो सबसे पहले चीनी और शराब को ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। मगर आपके किचन के डिब्बों में रखी कुछ बेहद साधारण चीजें चीनी से भी ज्यादा नुकसानदायक हैं जो फैटी लीवर के जोखिम को कई गुना बढ़ा रही हैं? फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त फैट जमा हो जाती है, जो धीरे-धीरे लीवर में सूजन और सिरोसिस का कारण बन सकती है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हम जानें-अनजाने में ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं जो लीवर पर मेटाबॉलिक बोझ बढ़ा देते हैं। जब लीवर इन जटिल तत्वों को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वह उन्हें फैट के रूप में स्टोर करने लगता है। इसलिए केवल चीनी छोड़ना काफी नहीं है, लीवर को सुरक्षित रखने के लिए किचन के उन चीजों की भी पहचान करना जरूरी है जो दबे पांव आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मैदा और रिफाइंड कार्ब्स

चीनी की तरह ही मैदा और उससे बने उत्पाद जैसे बिस्कुट, सफेद ब्रेड और पास्ता लीवर के लिए नुकसानदायक हैं। इनमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे ये शरीर में जाकर तेजी से ग्लूकोज में बदल जाते हैं। जब खून में अचानक ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो लीवर इसे फैट में बदल देता है, जिससे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। मैदा शरीर पर कई तरह से हानिकारक प्रभाव डालता है। सबसे पहले यह पाचन तंत्र पर भारी पड़ता है। आंतों में जाकर यह गोंद जैसी परत बना लेता है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे यह तुरंत ब्लड शुगर बढ़ाता है और डायबिटीज के रोगियों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है।

नमक का अधिक सेवन

किचन में मौजूद नमक का अत्यधिक सेवन सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि फैटी लीवर के जोखिम को भी बढ़ा देता है। प्रोसेस्ड स्नैक्स, अचार और डिब्बाबंद खानों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत अधिक सोडियम शरीर में फ्लुइड रिटेंशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। यह लीवर की कोशिकाओं में स्कारिंग की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे लीवर डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है।

ट्रांस फैट और वनस्पति घी

घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वनस्पति घी और दोबारा गरम किया गया तेल ट्रांस फैट का भंडार है। ट्रांस फैट्स न केवल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बल्कि लीवर में सूजन पैदा करते हैं। समोसे, कचोरी या बाहर के तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से समस्याएं बढ़ती हैं क्योंकि इसमें मौजूद फैट सीधे लीवर के टिशूज में जमा हो जाते हैं, जिसे पचाना शरीर के लिए लगभग असंभव हो जाता है।

बचाव के लिए क्या करें?

फैटी लीवर से बचने के लिए मैदा की जगह होल ग्रेन (जैसे ओट्स, बाजरा) और रिफाइंड तेल की जगह कोल्ड-प्रेस्ड तेल का चुनाव करें। अपने भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और सक्रिय जीवनशैली अपनाएं। ध्यान रखें लीवर आपके शरीर का फिल्टर है, यदि आप इसे साफ रखेंगे, तो यह पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा।

हंसना मना है

लड़का-मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लड़की का बाप- कितना कमा लेते हो। लड़का- 19000 हजार महीना। लड़की का बाप- 15000 मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी देता हूं। लड़का- वो मिलाके के ही बोल रहा हूं अंकल।

पत्नी: हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा.. पति -अरे उसमें डॉक्टर को क्या बताना! वो तो जितना है उतना दुखेगा ही। बस तब से ही पति का पूरा बदन दु:ख रहा है।

पति अपनी पत्नी से- मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी- ठीक है, कुछ देर बाद, पति- मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या, पत्नी- नहीं अभी नहीं, पति- क्यों? पत्नी - अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही, तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं। पति बेहोश।

फादर- अगर इस बार तुम इम्तिहान में फेल हुए तो मुझे पापा मत कहना। इम्तिहान के बाद, फादर-तुम्मारा रिजल्ट कैसा रहा? सन: दिमाग का दही मत कर बाबूलाल तु बाप कहलाने का हक खो चुका है।

पति बाल्कनी में खड़ा-खड़ा मस्ती से गा रहा था। पंछी बनूं उड़ता फिरुं मस्त गगन में.. आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में..रसोई में से बीवी की आवाज आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है...

कहानी — श्री कृष्ण और कालिया नाग

श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर-चूर कर दिया था, यह बात तब की है जब यशोदा के लला कहैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु-पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते-खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते-खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था। इसलिए, मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूं। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुंचे और यशोदा मैया को कहैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं। यह बात धीरे-धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े-दौड़े यमुना नदी के किनारे आए गए, लेकिन कृष्ण अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं, नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद् हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — पुराना रोग उभर सकता है। योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे।

वृषभ — व्यवसाय में ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ समय न गंवाएं। पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। थकान रहेगी। कुसंगति से बचें।

मिथुन — घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

कर्क — कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति निर्मित होगी। प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें।

सिंह — बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। समय पर कर्ज चुका पाएंगे।

कन्या — पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। लाभ होगा।

तुला — दूर से बुरी खबर मिल सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। बेवजह तनाव रहेगा। किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। फालतू बातों पर ध्यान न दें। व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिक — कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। चिंता बनी रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी।

धनु — उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बड़ा काम करने का मन बनेगा।

मकर — नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति संभव है। यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। निवेश शुभ रहेगा।

कुम्भ — फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। आय होगी। संतुष्टि नहीं होगी।

मीन — यात्रा लाभदायक रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। संचित कोष में वृद्धि होगी।

बॉलीवुड | मन की बात

सूबेदार फिल्म मेरे लिए बहुत खास है : अनिल कपूर

अनिल कपूर की मच-अवेटेड फिल्म सूबेदार अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए तैयार है। सोमवार को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस मौके पर अनिल कपूर ने सूबेदार में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। अनिल कपूर ने कहा, यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। यह रोल मेरे लिए मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग रोल में से एक है। मैंने इसे हमेशा की तरह पूरे दिल और जान से किया है। मैंने अपनी तरफ से कड़ी मेहनत की है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म और हमारा काम पसंद आएगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अनिल कपूर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के रोल में हैं। वह एक शहर में आते हैं, जहां गुंडाराज चल रहा है। मोना सिंह एक माफिया यानी दीदी के रोल में हैं। उसका एक भाई है, जो लोगों पर जुल्म करता है। एक दिन वह अनिल कपूर की बेइज्जती कर देता है। उसके बाद एक्शन शुरू होता है। 'सूबेदार' एक एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है। इसमें अनिल कपूर के अलावा मोना सिंह, राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, आदित्य रावल, फैजल मलिक और खुशबू सुंदर भी हैं। यह फिल्म 5 मार्च को स्ट्रीम होगी। 'सूबेदार' के अलावा अनिल कपूर कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। वह पिछले साल फिल्म वॉर 2 में नजर आए थे। वह इस साल अल्फा और किंग फिल्म में भी नजर आएंगे। दोनों ही फिल्में इसी साल रिलीज होंगी। किंग फिल्म में अनिल कपूर के अलावा कई नामी एक्टर्स भी नजर आएंगे।

एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही सनी देओल की बॉर्डर 2

सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और ये अब भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है। यहां तक कि अस्सी, दो दीवाने सहर में और ओ रोमियो जैसी नई फिल्मों के आने के बावजूद 'बॉर्डर 2' खूब कमाई कर रही है। इसने पांचवें वीकेंड खूब नोट कमाए थे। चलिए यहां जानते हैं वॉर ड्रामा ने पांचवे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। ये वॉर ड्रामा साल 2026 में बॉलीवुड की पहली बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है। इस वॉर ड्रामा ने रिलीज के पहले हफ्ते में धमाकेदार कमाई की थी इसके बाद इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट बनी रही लेकिन फिर भी ना केवल इसने अपना 275 करोड़ का बजट वसूल किया बल्कि

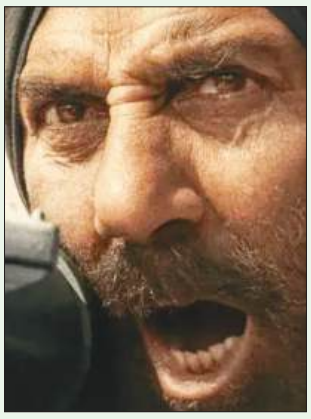

रिलीज के 32 दिनों में मोटा मुनाफा भी कमा लिया।

फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालें तो इसने 30 करोड़ से ओपनिंग की थी। इसके बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ कमाए। दूसरे वीक का कलेक्शन 70.15 करोड़ रुपये रहा और तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23.35 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि चौथे हफ्ते की कमाई 6.16 करोड़ रही। वहीं इसके बाद 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 29वें दिन 0.13 करोड़, 30वें दिन 0.55 करोड़ और 31वें दिन 0.7 करोड़ का कारोबार किया।

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 32वें दिन यानी 5वें मंडे को 0.24 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ 'बॉर्डर 2' की 32 दिनों की कुल कमाई अब 326.14 करोड़ रुपये हो गई है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म 275 करोड़ के बजट में बनी है और 31 दिनों में इस फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 326.14 करोड़ कमाए हैं ऐसे में मेकर्स ने 51.14 करोड़ का रिटर्न कमाया है। बता दें कि बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है।

ओटीटी नहीं थियेटर में ही रिलीज होगी आलिया भट्ट की अल्फा

आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इस फिल्म में शरवरी वाघ भी होंगी। फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थीं। हालांकि, पेंडिंग काम के चलते आलिया की स्पाई एक्शन थ्रिलर पोस्टपोन हो गई। फिल्म को यश राज फिल्म्स बना रहे हैं। यश राज फिल्म की पिछली दो स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर अंडरपरफॉर्म किया था। इसी वजह से अल्फा पर भी काफी प्रेशर है। बीच में खबरें आई थीं कि मेकर्स फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का ऑप्शन तलाश रहे थे।

हालांकि, Variety India की अब खबर है कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स की 215 करोड़ की डील को रिजोक्ट कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने 215 करोड़ का ऑफर दिया था कि फिल्म डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाए। लेकिन मेकर्स ने ये रिजेक्ट कर दिया और अब फिल्म सीधे थिएटर में रिलीज होगी। YRF के स्पोक्सपर्सन ने बताया, यश राज फिल्म कभी भी अपनी फिल्म को थिएटर रिलीज की बजाय डायरेक्ट ओटीटी पर स्ट्रीम नहीं करेंगे। हम स्टूडियो हैं जिसे सिनमैटिक एक्सपीरियंस बनाने को लेकर गर्व है। अल्फा कंपनी की बहुत अहम फिल्म है।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि यश राज फिल्म ने डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट किया हो। कोविड के समय में भी यश राज फिल्म थिएटर सेक्टर के साथ खड़ा था।

फिल्म अल्फा को शिव रवैल डायरेक्ट कर रहे हैं। ये यश राज स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ-साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन के भी कौमियो अपीरियंस की खबरें हैं। फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है। आलिया भट्ट की बात करें तो उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट्स हैं। वो अल्फा के अलावा फिल्म लव एंड वॉर में भी दिखेंगी।

अजब-गजब | अमेजन के घने जंगलों में रहती है अजीब जनजाति

इस जनजाति के पास नहीं है समय का कोई ज्ञान ये लोग जिंदगी में कई बार बदलते हैं अपना नाम!

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां हर सेकंड की कीमत है। घड़ी की सुइयां हमारे उठने, सोने और काम करने का फैसला करती हैं। लेकिन अमेजन के घने जंगलों में रहने वाली अमुंदावा जनजाति के लिए समय का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में 'समय' शब्द ही नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन बता दें कि ब्राजील के अमेजन वर्षावनों में रहने वाली इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता के सबसे बुनियादी आधार यानी 'समय' को ही नकार दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के शोधकर्ताओं ने जब इस जनजाति पर गहराई से रिसर्च की, तो वे यह जानकर दंग रह गए कि अमुंदावा भाषा में समय, सप्ताह, महीने या साल जैसे शब्दों के लिए कोई अनुवाद मौजूद ही नहीं है। इनके लिए बस सूरज का उगना और डूबना ही काफी है। ये लोग पूरी तरह से आज में जीते हैं और इन्हें कल की कोई परवाह नहीं होती।

इस जनजाति के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि इनके यहां किसी की उम्र का हिसाब नहीं रखा जाता। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, अगर आप किसी अमुंदावा से पूछेंगे कि वह कितने साल का है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। यहां उम्र को नंबरों

में नहीं नापा जाता, बल्कि पहचान से जोड़ा जाता है। जब इस जनजाति का कोई बच्चा बड़ा होता है, तो उसका नाम बदल दिया जाता है यानी नाम बदलना ही इस बात का सबूत है कि वह व्यक्ति अब बड़ा हो गया है। यहां एक इंसान अपने पूरे जीवन में कई बार अपना नाम बदलता है। यह तरीका हमें सिखाता है कि बिना नंबरों के भी समाज को चलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इनकी भाषा को गहराई से समझा, तो पाया कि अमुंदावा लोग 'समय बीत रहा है' जैसी बात समझ ही नहीं पाते। उनके लिए वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे पकड़ा जा सके या जिसका हिसाब रखा जा सके। उन्हें घड़ी या कैलेंडर की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई।

जब पहली बार बाहरी दुनिया के लोगों ने इनसे संपर्क किया, तो वे इन्हें समझा ही नहीं पाए कि 'बर्थडे' या 'उम्र' क्या होती है। इनके यहां न तो कोई काम करने की डेडलाइन होती है और न ही कहीं पहुंचने की जल्दबाजी। शायद यही वजह है कि ये लोग आधुनिक दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा शांत और खुश रहते हैं। अब जब यह जनजाति धीरे-धीरे बाहरी दुनिया और तकनीक के संपर्क में आ रही है, तो उनके सामने अजीब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जब सरकार इनके आईडी कार्ड या पासपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, तो जन्म की तारीख लिखना नामुमकिन हो जाता है। इन्हें अब पुर्तगाली भाषा सिखाई जा रही है, ताकि ये दुनिया के साथ चल सकें। लेकिन इसके साथ ही डर यह भी है कि कहीं इनकी यह अनोखी और सुकून भरी संस्कृति खत्म न हो जाए। इनके पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कुदरत के इशारों को हमसे बेहतर समझते हैं। अगर खाने-पीने की बात करें, तो अमुंदावा पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। ये बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं। ये लोग तीर-धनुष का इस्तेमाल करके छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके अलावा अमेजन की नदियों से मछली पकड़ना इनके भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। ये लोग जंगली फल, कंद-मूल और शहद भी इकट्ठा करते हैं।

दुनिया की वो नदी, जो एक साथ बहती है दो दिशाओं में, अनसुलझा है रहस्य

नदियां हमेशा से प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक रही हैं। ये पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक बहती हैं, जीवन देती हैं और कभी-कभी ऐसे रहस्य छुपाती हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे हैं। आमतौर पर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं। ऊंचाई से नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी एक नदी है जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में बहती है? जी हां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि कनाडा की इचिमामिश नदी का वास्तविक रहस्य है। स्थानीय भाषा में इसका नाम ही 'पानी जो दोनों तरफ बहता है' रखा गया है। यह नदी कनाडा के जंगलों में बहती है और यहां से पानी एक तरफ हडसन बे की ओर जाता है, तो दूसरी तरफ अलग दिशा में। वैज्ञानिक इसे 'रिवर बिफुरकेशन' कहते हैं, जहां एक नदी दो या ज्यादा शाखाओं में बंट जाती है। लेकिन इचिमामिश का मामला अलग है। यहां ढाल इतनी कम है (0.009 प्रतिशत से भी कम) कि पानी दोनों दिशाओं में कैसे बहता है, ये समझना मुश्किल है। NASA ने भी इस नदी की सैटेलाइट तस्वीरें ली हैं, जो इसकी अनोखी प्रकृति को दर्शाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये घटना तब होती है जब एक नदी दूसरी नदी का पानी आंशिक रूप से कैप्चर कर लेती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसे 'इनकम्पलीट रिवर कैप्चर' कहा जाता है। लेकिन इचिमामिश में ये प्रक्रिया इतनी परफेक्ट है कि पानी दोनों ओर बराबर बहता रहता है। हाल के अध्ययनों में अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की कई ऐसी नदियों का जिक्र है जो हाइड्रोलॉजी के नियम तोड़ती नजर आती हैं। जैसे वेनेजुएला और सूरीनाम में कुछ नदियां अप्रत्याशित तरीके से बंटती हैं। लेकिन इचिमामिश सबसे ज्यादा रहस्यमयी है क्योंकि इसका ढाल न्यूनतम है, फिर भी पानी का प्रवाह मजबूत है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्राकृतिक 'वर्महोल' जैसा है। जहां पानी दो अलग वाटरशेड में बंट जाता है। इस राज को सुलझाने के लिए कई स्टडी की जा चुकी है। एक अध्ययन में इसे 'हाइड्रोलॉजिक इक्विवेलेंट ऑफ ए वर्महोल बिटवीन टू गैलेक्सीज' तक कहा गया है। वैज्ञानिकों ने 9 ऐसी अनियमित नदियों और झीलों का विश्लेषण किया, जहां पानी अपेक्षित नियमों के विपरीत बहता है। इचिमामिश इसमें सबसे ऊपर है। भारत में भी ऐसी कहानियां हैं। नर्मदा नदी को उल्टी बहने वाली नदी कहा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व जाती हैं।

राजस्थान विस में बीकानेर रेप-मर्डर केस पर मचा बवाल

कांग्रेस का वॉकआउट, गृह मंत्री ने जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा

» विपक्ष बोला- कातिल कब पकड़े जाएंगे, स्पीकर की सख्त टिप्पणी से और गरमाया माहौल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बीकानेर में नाबालिग के कथित रेप और मर्डर के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ज़ीरो आवर के दौरान विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया जिससे राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सदन में अनुशासन बनाए रखने की अपील की, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं दिखा। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लगातार हो रही तीखी नोकझोंक के बीच अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मनीष यादव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए बुलाया लेकिन उनके वॉकआउट और फिर वापस आने पर स्पीकर ने कड़ी नाराजगी जताई। देवनानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा आप एक ही समय पर वॉकआउट भी करना चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है और सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि बीकानेर में शनिवार को एक 13 वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अपनी कक्षा 8 की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। बाद में उसका शव जंगल के पास मिला, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

13 वर्ष की बच्ची की रेप के बाद की गयी हत्या: कांग्रेस विधायक

ज़ीरो आवर में कांग्रेस विधायक डूंगाराम गेदर ने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एक 13 वर्षीय मासूम के साथ हुई इस जघन्य घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर अब तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी और जांच में देरी क्यों हो रही है। गेदर ने कहा कि अगर सरकार गंभीर होती तो अब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया होता। इस पर राज्य के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने सदन को आश्वस्त किया कि पुलिस पूरी तत्परता से जांच कर रही है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नाबालिग का शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखा गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

टीका राम जूली ने लगाये गंभीर आरोप

विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में पूछा सरकार बताए कि कातिल कब पकड़े जाएंगे? जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहिए। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष पर इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और विपक्ष को जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। इस पर गृह मंत्री बेधम ने भी विपक्ष के रवैये को सस्ती पॉलिटिक्स करार दिया, जिससे सदन का माहौल और गरमा गया।

झारखंड में मतदान खत्म, अब नतीजों का इंतजार

» निकाय चुनाव में रांची में सबसे कम तो सरायकेला में पड़े सबसे अधिक वोट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। झारखंड के 48 नगर निकायों में सोमवार को हुए मतदान में शाम 5 बजे तक कुल 61.83 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक मतदान सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला नगर पंचायत में 75.35 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि रांची नगर निगम में सबसे कम 43.28 प्रतिशत वोट पड़े। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि मतदान के आंकड़ों की अंतिम गणना के बाद मत प्रतिशत में इजाफा होने की संभावना है। सर्वाधिक मतदान वाले निकायों की बात करें तो दुमका जिले के बासुकीनाथ नगर पंचायत में 74.18 प्रतिशत, रांची जिले के बुण्डू नगर पंचायत में 74 प्रतिशत तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया नगर पंचायत में 72.90 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

चुनाव अधिकारी के मुताबिक इससे स्पष्ट है कि छोटे नगर निकायों, विशेषकर नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह अधिक रहा। बड़े शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी देखने को मिली। मेदिनीनगर नगर निगम में 57.41, देवघर नगर निगम में 52.92, धनबाद नगर निगम में 48 प्रतिशत, बोकारो जिले के चास नगर निगम में 49.76 प्रतिशत तथा हजारीबाग नगर निगम में 49.9 प्रतिशत मतदान हुआ। नगर निगमों में गिरिडीह नगर निगम 60 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा। नगर परिषद श्रेणी में चतरा नगर परिषद में सर्वाधिक 68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि साहेबगंज नगर परिषद में सबसे कम 57.58 प्रतिशत मतदान हुआ। अन्य अधिकांश नगर परिषदों में मतदान 60 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक रहा। उन्होंने कहा कि राज्य के 4307 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी और दोपहर बाद मतदान में तेजी देखने को मिली। सुबह 9 बजे 10.50 प्रतिशत से आरंभ हुआ मतदान 11 बजे तक 23.23 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 37.44 प्रतिशत और 3 बजे तक 50.61 प्रतिशत पहुंच गया।

तमिलनाडू में कांग्रेस ने जताया ज्यादा सीटों पर हक

» वेणुगोपाल-स्टालिन मीटिंग के बाद गिरीश चोडनकर ने गठबंधन पर की बातचीत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नाई। एआईसीसी तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडनकर ने बताया कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 2021 में मिली सीटों से अधिक विधानसभा सीटों की मांग की है। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बीच हुई मुलाकात के बाद दी। चोडनकर ने बताया कि इस बातचीत में सीट-शेयरिंग व्यवस्था, जिसमें एक राज्यसभा सीट का आवंटन, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समन्वय शामिल था। उन्होंने कहा, पार्टी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रही है।

2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गठबंधन के हिस्से के तौर पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले चोडनकर, टीएनसीसी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई और डीएमके की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एवं लोकसभा सांसद कनिमोझी करुणानिधि से उनके घर पर मिले थे। उन्होंने इस बैठक को कर्टसी कॉल बताया और कहा कि गठबंधन पार्टनर्स के बीच बातचीत अलग-अलग समितियों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। चोडनकर ने पावर-शेयरिंग व्यवस्था पर कहा कि चुनाव क्षेत्र-शेयरिंग अभी सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया, सबसे पहले हमें सीट-शेयरिंग पर सहमति बनानी होगी, बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

दिल्ली में तीन महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार

» गुस्से में मेघालय के सीएम, कहा- अरुणाचल की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने सोमवार को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। संगमा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और गरिमा पर चिंता व्यक्त की और समाज और अधिकारियों से अधिक संवेदनशीलता और जवाबदेही की मांग की।

शिलांग में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश के हमारे पूर्वोत्तर

नागरिकों के साथ हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आज के समाज में अस्वीकार्य है। सीएम ने कहा है कि घटना के दौरान इस्तेमाल की गई कथित भाषा, शब्द और व्यवहार एक परेशान करने वाली मानसिकता को दर्शाते हैं और इस क्षेत्र से बाहर रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली निरंतर चुनौतियों को उजागर करते हैं। संगमा ने कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यहां तक कि शारीरिक हावभाव भी बहुत परेशान करने वाला और पूरी तरह से अस्वीकार्य था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और देश के सभी क्षेत्रों के नागरिक, चाहे वे कहीं भी रहते हों, सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी

संगमा ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नस्लीय दुर्व्यवहार की घटनाएं एकता, समावेशिता और विविधता की भावना को कमजोर करती हैं, जो भारत की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग देश भर के शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर इस देश का अभिन्न अंग है, और इसके लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

अब फुटबाल के नये नियमों से नाराज हुए प्रेसीडेंट ट्रंप

» कहा- यह बहुत खराब नियम है, खेल की दिशा पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुटबॉल में लागू किए गए नए नियमों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बहुत खराब करार दिया है। हाल ही में पेश किए गए बदलावों को लेकर उन्होंने कहा कि ये नियम खेल की पारंपरिक भावना को कमजोर करते हैं और दर्शकों के उत्साह को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद खेल और राजनीति, दोनों ही हलकों में बहस छिड़ गई है। फुटबॉल में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव किए गए हैं।

इनमें खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ टैकलिंग तकनीकों पर सख्ती, वीडियो रिव्यू सिस्टम के दायरे का विस्तार और रेफरी के निर्णयों में तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना शामिल है। खेल संचालक संस्था एनएफएल का कहना है कि इन बदलावों का मकसद खिलाड़ियों को गंभीर चोटों से बचाना और खेल को अधिक निष्पक्ष बनाना है। प्रेसीडेंट का मानना है कि अत्यधिक नियम और तकनीकी दखल खेल की रफ्तार और रोमांच को कम कर देंगे। उन्होंने कहा, फुटबॉल अपनी सख्ती और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा नियंत्रित करेंगे, तो वह वैसा नहीं रहेगा जैसा लोग पसंद करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि दर्शक खेल में स्वाभाविकता और तेज़ी देखना चाहते हैं, न कि हर कुछ मिनट में रुकावट। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में खिलाड़ियों में सिर की चोटों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण नियमों में बदलाव आवश्यक हो गए थे। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की मांग की थी। इसी संदर्भ में एनएफएल ने कुछ आक्रामक टैकल्स पर प्रतिबंध और हेलमेट-टू-हेलमेट संपर्क पर कड़ी सजा का प्रावधान लागू किया है।

ट्रंप की टिप्पणी से नई बहस शुरू

फिलहाल, ट्रंप की टिप्पणी ने फुटबॉल के बदलते स्वरूप पर नई बहस छेड़ दी है। यह बहस सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सवाल तक पहुंचती है कि क्या आधुनिक खेल परंपरा और तकनीक के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं। आने वाले सीज़न में यह देखना दिलचस्प होगा कि नए नियम खेल की गुणवत्ता, दर्शकों की रुचि और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर किस तरह असर डालते हैं और क्या ट्रंप की आशंकाएं सही साबित होती हैं या नहीं।

भोपाल में कांग्रेस की महाचौपाल

राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में भरी हुंकार

» खरगे भी हुए शामिल, ट्रेड डील का सबसे ज्यादा असर भोपाल के किसानों पर

» वैश्विक साझेदारी या आत्मनिर्भरता पर हमला?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल को लेकर आज बड़ा राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यह कार्यक्रम भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आयोजित किया गया है और इसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय किसान आंदोलन की शुरुआत का मंच बनाया है। कार्यक्रम भोपाल के जवाहर चौक पर आयोजित किया जा रहा है जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील की बखिया उधेड़ते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि और आर्थिक मजबूती का प्रतीक बता रही है लेकिन इसके समानांतर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान आकार ले रहा है।

विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे भारत के किसानों छोटे उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह डील भारत के बाजार को अमेरिकी कॉर्पोरेट और कृषि उत्पादों के लिए खोल देगी, जिससे देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसान असमान प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे। इसी खतरे को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस ने आज भोपाल से राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन की शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किसानों के बीच पहुंचकर अपनी बता रखी।

छोटे किसानों पर सबसे बड़ा खतरा : असमान प्रतिस्पर्धा की चुनौती

भारत के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और छोटे किसानों की संख्या है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर, अत्याधुनिक तकनीक और भारी सरकारी सब्सिडी के सहारे होती है। वहां के किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जबकि भारत के किसान सीमित संसाधनों और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। अगर ट्रेड डील के तहत अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दामों पर आने लगे, तो भारतीय किसानों की फसल की कीमत गिर सकती है। इससे उनकी आय में भारी गिरावट आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि यह स्थिति लाखों किसानों को कर्ज और आर्थिक संकट की ओर धकेल सकती है।

किसान महाचौपाल बनेगी राष्ट्रीय मंच

कांग्रेस भोपाल में आयोजित होने वाली किसान महाचौपाल को सिर्फ एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।मध्य प्रदेश को इस अभियान के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां करीब 80 लाख किसान परिवार हैं जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत सीमांत किसान हैं। और यह वह किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और जिनकी आजीविका पूरी तरह स्थानीय बाजार और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्भर करती है। कांग्रेस का मानना है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में कम शुल्क पर आने लगे तो स्थानीय किसानों के लिए अपनी उपज बेचना लगभग असंभव हो जाएगा। महाचौपाल के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनाना चाहती है और यह संदेश देना चाहती है कि यह डील सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट भी पैदा कर सकती है।

छोटे उद्योग और स्थानीय बाजार पर भी संकट के बादल

यह डील सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। छोटे और मध्यम उद्योग भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। भारत के लाखों छोटे उद्योग स्थानीय बाजार पर निर्भर हैं। अगर अमेरिकी कंपनियों को भारत में अधिक छूट मिलती है, तो वे सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पाद बेचकर स्थानीय उद्योगों को पीछे छोड़ सकती हैं। इससे रोजगार पर भी गंभीर असर पड़ेगा। छोटे उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी गरीबों पर पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि यह डील मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दावों के विपरीत है।

8 लाख की उड़ान फिर भी बुझ गई जिंदगी

» रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश सात की मौत

» डीजीसीए ने दिये जांच के आदेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली इलाज के लिए ले जाए जा रहे 41 वर्षीय संजय कुमार के लिए एयर एंबुलेंस सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि जीवन और मौत के बीच आखिरी पुल थी।

लातेहार जिले के चंदवा निवासी संजय पिछले 6-7 दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। 65 प्रतिशत तक जल चुके संजय का इलाज रांची के देवकमल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी जान बचाने की एकमात्र उम्मीद बेहतर सुविधाओं वाले दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट करना है।

परिजनों ने तुरंत रेडबर्ड एयरवेज की एयर एंबुलेंस बुक की। कुल खर्च 8 लाख रुपये तय हुआ। परिवार ने किसी तरह 5.5 लाख रुपये एडवांस जमा कर दिए लेकिन उड़ान से ठीक पहले कंपनी ने शेष ढाई लाख रुपये की मांग करते हुए साफ कह दिया कि पूरी रकम के बिना एयर एंबुलेंस उड़ान नहीं भरेगी। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।

यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरहमी का प्रतीक बना

संजय के परिवार के लिए यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरहमी का प्रतीक बन गया। एक ऐसा सिस्टम, जहां इलाज की उम्मीद भी पैसों की शर्तों में बंधी होती है। जहां एक मरीज की सांसें भी बैंक बैलेंस से तय होती हैं। आज चंदवा का वह घर मातम में डूबा है जहां से एक बेटा पति और पिता जिंदगी की उम्मीद लेकर निकला था। लेकिन वह उम्मीद आसमान में ही बुझ गई। पीछे रह गया है सिर्फ एक सवाल अगर उड़ान वक्त पर भर जाती अगर पैसे की शर्त रास्ता न रोकती तो क्या संजय आज जिंदा होते?

एक तरफ संजय की बिगड़ती हालत दूसरी तरफ पैसों की व्यवस्था का असहनीय दबाव। हर सेकंड भारी होता जा रहा था। मजबूरी में परिजन गांव लौटे रिश्तेदारों और परिचितों के सामने हाथ फैलाए और किसी तरह ढाई लाख रुपये का इंतजाम किया। जब तक पैसे जुटे और वापस रांची पहुंचकर जमा किए गए तब तक जिंदगी की घड़ी काफी आगे बढ़ चुकी थी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर भाजपा को पड़ेगी भारी : अजय राय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि संतों और धार्मिक गुरुओं के खिलाफ कार्रवाई कर भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है और सत्ता के दुरुपयोग के जरिए विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का राजनीतिक नुकसान भाजपा को आने वाले समय में जरूर उठाना पड़ेगा।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं और धार्मिक परंपराओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संत या सामाजिक व्यक्ति सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार आलोचना सहन करने की स्थिति में नहीं है। अजय राय ने कहा कि संत समाज भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मेरठ में दर्दनाक हादसा, 5 बच्चों समेत 6 लोगों की जलकर मौत

» कपड़ा कारोबारी के घर में लगी भीषण आग से पसरा मातम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मेरठ में एक कप?ा कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से उसके परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में जुड़वां बेटियों समेत 5 मासूम बच्चे शामिल हैं।

यूपी पुलिस ने बताया कि मेरठ जिले में सोमवार रात एक रिहायशी घर में आग लगने से पांच बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। आग लगने पर घर के अंदर फंसने से दो महिलाएं और पांच बच्चे बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पांच बच्चों और एक महिला की बाद में मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि कारोबारी सोमवार की देर शाम नमाज प?ने गया था, तभी दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। उस

वक्त उसके घर में 2 महिलाएं और 5 बच्चे मौजूद थे। सभी आग की तेज लपटों में फंस गए। अधिकारियों के मुताबिक, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल कपड़ों के गोदाम के तौर पर किया जा रहा था। जबकि परिवार ऊपरी फ्लोर पर रहता था। मेरठ पुलिस ने बताया कि घटना के समय इकबाल नाम का एक रहने वाला अपने भाई के साथ शाम की नमाज के लिए बाहर गया था। जबकि दो औरतों और बच्चों को घर पर छोड़ गया था। पड़ोसियों ने घर से आग और धुआं निकलता देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को बताया। फायरफाइटर्स और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया।

उदय भानु गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा 4 दिन की पुलिस कस्टडी में

एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पार कर शर्टलेस होकर किया था विरोध प्रदर्शन

» इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भानु चिब

» राहुल गांधी ने चिब की गिरफ्तारी पर उठाये सवाल कहां यह तानाशाही का प्रमाण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली की सियासी हलचल के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को आ सुबह गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट मे पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे एआई समिट के दौरान हुए विवादित प्रदर्शन को अदालत ने गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस को विस्तृत पूछताछ की अनुमति दी है।

कोर्ट के इस फैसले ने न केवल कांग्रेस के युवा नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक विरोध, सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। अब आने वाले चार दिन इस मामले की दिशा और सियासी असर दोनों तय करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने चिब की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। चिब की गिरफ्तारी तानाशाही का परिणाम हैं।

शांतिपूर्ण हो रहा था प्रदर्शन

चिब के वकील के मुताबिक प्रदर्शनकारी निहत्थे थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बचाव पक्ष के अनुसार, सात-आठ टी-शर्ट पहले ही बरामद की जा चुकी हैं और टी-शर्ट कहीं भी छप सकती हैं, ऐसे में पूरी फैक्ट्री की जांच का तर्क बेबुनियाद है। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को मंगलवार सुबह हिरासत में लिया था। इसके पहले उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा